

# समाचार वाणी

## खबर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 22 September 2026

**महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव मे गठबंधनों का घालमेल : क्या बीएमसी चुनाव का ट्रैलर दिखा रहे हैं बंदलते समीकरण ?**

Publisher

Published on 21 Nov 2025



महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां मित्र और विरोधी की लकीरें पहले से कहीं ज्यादा धुंधली हो चुकी हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में राजनीतिक दलों ने जिस तरह के स्थानीय गठबंधन बनाए हैं, उसने राज्य की राजनीति के पुराने समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। मुंबई की राजनीति में बीएमसी चुनाव को लेकर जो उत्सुकता है, वह इन जिला परिषद परिणामों से और बढ़ गई है। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इन लोकल चुनावों में दिखा यह घालमेल दरअसल मुंबई महानगरपालिका चुनावों का 'ट्रेलर' है, जहां गठबंधन की सीमाएं टूटती दिख रही हैं और हर पार्टी अपने दम पर मैदान में उतरने की तैयारी में है।

महाराष्ट्र में इस बार जिला परिषद चुनाव केवल ग्रामीण राजनीति का मामला नहीं रहा, बल्कि उसने पूरे राज्य के राजनीतिक गठबंधन ढांचे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एमवीए (शिवसेना-यूबीटी, कांग्रेस, शरद Pawar गुट) और महायुति (भाजपा, शिंदे सेना, अजित Pawar गुट) के बीच जो बड़े गठबंधन बने थे, वे जमीनी स्तर पर बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। चुनावी इलाके में पार्टियों के स्थानीय नेताओं ने अपने-अपने स्वार्थ और समीकरणों के हिसाब से ऐसे गठबंधन किए हैं जिनकी कल्पना बड़े नेताओं ने भी नहीं की थी।

सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर चांदगढ़ से सामने आई, जहां अजित पवार गुट और शरद पवार गुट एक साथ मिलते दिखे। पारिवारिक विभाजन के बाद दोनों गुटों की राहें पूरी तरह अलग हो चुकी थीं, लेकिन जिला परिषद चुनाव में यह साथ मिलकर लड़ना एक अलग ही राजनीतिक संदेश देता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह गठबंधन स्थानीय समीकरणों की मजबूरी हो सकती है, लेकिन इससे राज्य स्तर के नेताओं की रणनीति को प्रभावित करना तय है।

पुणे के चाकण क्षेत्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना एक साथ मैदान में नजर आई। यह चुनावी गठबंधन उस शिवसेना विभाजन के बिल्कुल विपरीत है जिसने 2022 में महाराष्ट्र की राजनीति को हिला दिया था।

दोनों गुटों का एक साथ आना कई लोगों के लिए हैरानी का विषय रहा, क्योंकि राजनीतिक रूप से दोनों धड़ों के बीच खुला संघर्ष जारी है। लेकिन स्थानीय मतदाताओं को साधने के लिए नेताओं ने यह 'समझौता' किया है। इससे संकेत मिलता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कई स्तरों पर गठबंधन की परतें मौजूद हैं, जो हर बार अलग ढंग से खुलती हैं।

पालघर में तस्वीर और भी रोचक हो गई है। यहां शिंदे सेना और एनसीपी के दोनों गुट एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं। यह गठबंधन न केवल महायुति में 'दरार' का संकेत देता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि चुनावी लाभ के लिए पार्टियां अपने बड़े राजनीतिक गठबंधनों से हटकर भी फैसले ले सकती हैं। बीजेपी, जो महायुति में मुख्य नेतृत्व वाली पार्टी है, स्थानीय स्तर पर इस तरह की चुनौतियों से असहज महसूस कर रही है।

इन लोकल गठबंधनों पर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक नेताओं की चुप्पी भी कई सवाल पैदा कर रही है। न तो महायुति और न ही एमवीए के बड़े नेताओं ने इन बदलावों पर कोई सीधा बयान दिया है। इससे कयास लगाया जा रहा है कि पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने इस घालमेल को 'अस्थायी' बताते हुए इसे नजरअंदाज करने का फैसला लिया है, लेकिन बीएमसी जैसे बड़े चुनाव में ये दरारें बड़ी चुनौतियों का कारण बन सकती हैं।

मुंबई महानगरपालिका चुनाव राज्य की राजनीति के लिए हमेशा से सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि बीएमसी का बजट कई राज्यों के बजट से भी बड़ा है। शिवसेना ने लंबे वर्षों तक बीएमसी पर राज किया है, और यह चुनाव शिवसेना, भाजपा और एमवीए सभी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न रहेगा। जिला परिषद चुनावों में दिखी टूट और लोकल गठबंधनों की पहल ने यह संकेत दे दिया है कि बीएमसी चुनाव में किसी भी पार्टी के लिए एकजुट रहना आसान नहीं होगा।

कांग्रेस ने जिला परिषद चुनावों में अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह अकेले चुनाव लड़ेगी। इससे एमवीए गठबंधन की चुनावी रणनीति और पेचीदा हो गई है। कांग्रेस का यह फैसला बीएमसी चुनावों पर भी असर डाल सकता है क्योंकि एमवीए एक मजबूत विकल्प बनकर बीजेपी को चुनौती देना चाहता है, लेकिन कांग्रेस का अलग होना इस कोशिश को कमजोर कर सकता है।

महाराष्ट्र में हो रहे इन चुनावी उतार-चढ़ाव से साफ है कि आने वाले दिनों में गठबंधन राज की सीमाएं ढह सकती हैं और पार्टियों को अपनी एकल पहचान के साथ मतदाताओं के बीच उतरना पड़ सकता है। जिस तरह जिला परिषद चुनावों में पार्टियों ने लोकल स्तर पर समझौते और गठबंधन किए, उससे बीएमसी चुनाव का स्वरूप भी काफी हद तक तय होता दिख रहा है।

कुल मिलाकर, महाराष्ट्र जिला परिषद चुनावों का यह घालमेल न केवल स्थानीय राजनीति का परिणाम है, बल्कि यह आने वाले बीएमसी चुनाव का एक बड़ा संकेत है। राजनीतिक दलों के बीच जो दोस्ती-दुश्मनी की नई रेखाएं खिंच रही हैं, वे राज्य की राजनीति को नए मोड़ पर ले जा सकती हैं। गठबंधन की मजबूरियां और स्थानीय जरूरतें अब एक-दूसरे से टकरा रही हैं, और बीएमसी चुनाव में इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा।